सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 76 हजार करोड़ का नकद प्रोत्साहन

आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती : मोदी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को देश में सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दी। योजना के तहत छह साल में 76 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 1.75 लाख करोड़ का निवेश लाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे देश में नवोन्मेष व उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।

क्षेत्र के विस्तार के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जाएगा। आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में सेमीकंडक्टर वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के मकसद से कुल 2,30,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सूचना तकनीक एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेमीकंडक्टर चिप अहम होते हैं। फैसले से सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम निर्माण, डिजाइन, फैब्रिकेशन, जांच को विकसित करने में आसानी होगी। डिस्प्ले यूनिट कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकेंगी। प्रोत्साहन के रूप में नकद राशि मिलेगी। उत्पादन इकाई के खर्च का 25% सरकार देगी।

चीन पर कम होगी निर्भरता

इस फैसले से सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। भारत अपनी जरूरत का 80% आयात करता है। इसमें 62% से ज्यादा आयात चीन से होता है।

- *योजना में एमएसएमई विकास पर खास जोर है। सरकार चिप निर्माण व शोध के लिए दो साल में 20 नई इकाइयां स्थापित करेगी। इनका टर्नओवर पांच साल में 1,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। पहले से काम कर रही 100 कंपनियों को भी योजना का लाभ मिलेगा।*

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा, खर्च होंगे 1300 करोड़

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के उपयोग पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैबिनेट ने इनसे लेनदेन की प्रतिपूर्ति के लिए 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, सरकार इस माध्यम से खरीदारी पर डिजिटल भुगतान का शुल्क चुकाएगी।

- **देश में पिछले महीने 7.56 लाख करोड़ रुपयों का डिजिटल लेन-देन हुआ है।**

पीएम कृषि सिंचाई योजना अब 2025-26 तक प्रभावी

पीएम कृषि सिंचाई योजना अब 2025-26 तक प्रभावी रहेगी। इससे यमुना को निर्मल करने में मदद मिलेगी और इससे 45 साल से बाट जोह रहे लखवार व रेणुका बांध के निर्माण की राह भी खुलेगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, दोनों प्रोजेक्ट 1976 से लंबित थे। दिल्ली समेत एनसीआर के चार राज्यों की पेयजल समस्या का भी समाधान होगा।

- **93,068 करोड़ खर्च होंगे, इसमें राज्यों को 37,454 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता मिलेगी। 22 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ।**

चीन को झटका...घटेगी आयात निर्भरता

भारत अभी सेमीकंडक्टर की 80 फीसदी से ज्यादा जरूरत आयात के जरिये पूरी करता है। इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग और उत्पादन से भारत का सेमीकंडक्टर आयात जल्द कच्चे तेल से भी ज्यादा हो जाएगा। चीन अभी दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले कुल सेमीकंडक्टर का 20 फीसदी उत्पादन करता है। आईटी मंत्रालय के 2018 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के सेमीकंडक्टर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कुल आयात मे चीन की हिस्सेदारी 63.4 फीसदी रही थी।

सेमीकंडक्टर की मांग से और बढ़ेंगे अवसर

- इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के जानकारों का कहना है कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल वाहन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है।
- एक सेमीकंडक्टर बनाने में करीब 200 छोटी-मोटी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और एक भी प्रक्रिया में गड़बड़ी होने से करोड़ों का नुकसान हो सकता है।
- सिर्फ वाहन क्षेत्र की बात करें तो एक कार के निर्माण में 500-1,500 सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन में इसकी पांच गुना चिप की जरूरत होगी।
- चिप की कमी से दुनियाभर में इस साल 71 लाख वाहनों का कम उत्पादन होने का अनुमान है।
- 2022 के मध्य तक दुनियाभर में सेमीकंडक्टर की कमी बनी रहेगी।

भारत बनेगा दुनिया की सेमीकंडक्टर फैक्टरी

नई दिल्ली। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 200 से ज्यादा उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही दुनिया का संकट भारत अब दूर सकता है। सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के बाद दुनियाभर की कंपनियां यहां इकाई लगाने के लिए प्रेरित होंगी। इससे देश को विश्व की सेमीकंडक्टर फैक्टरी बनाने का लक्ष्य पूरा होगा।

पीएलआई योजना...ताइवान, अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों की कंपनियां लगाएंगी इकाई, बढ़ेगा उत्पादन व निर्यात

केंद्रीय आईटी एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहले ही कई विदेशी कंपनियों ने भारत में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए संपर्क किया है। नई योजना से ताइवान, अमेरिका, सिंगापुर सहित यूरोपीय देशों की कंपनियां भी यहां अपनी फैक्टरी लगाने की इच्छा जताएंगी। इस्राइल की टॉवर सेमीकंडक्टर, एपल की विनिर्माता कंपनी फॉक्सकॉन, सिंगापुर के एक समूह और इंटेल, मीडियाटेक व क्वालकॉम जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में उत्पादन के लिए प्रेरित होंगी। सरकार इन कंपनियों को न सिर्फ उत्पादन इकाई लगाने में मदद करेगी, बल्कि सालाना उत्पादन के आधार पर छह साल तक नकद प्रोत्साहन भी देगी। योजना की मदद से भारत में 9.5 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 5.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात भी बढ़ेगा। ब्यूरो

डिजिटलीकरण ने बढ़ाई सेमीकंडक्टर की जरूरत

अश्विनी वैष्णव के अनुसार, महामारी के बाद दुनियाभर में आपूर्ति व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा और सभी देश डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में लग गए। इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ी और सेमीकंडक्टर की जरूरत भी बढ़ती गई। कोविड-19 की पहली लहर के बाद इसके उत्पादन पर खास असर पड़ा। दूसरी ओर, दुनियाभर में उत्पादों की खपत में भी कमी आई। ऐसे में सेमीकंडक्टर उत्पादक कंपनियों ने सिर्फ उन्हीं उपकरणों के लिए इसका उत्पादन किया, जिनकी बिक्री महामारी के दौरान भी होती रही। हालांकि, हालात में सुधार के बाद अचानक सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ी गई, लेकिन उत्पादन कम होने से संकट बढ़ता गया और दुनियाभर में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री व असर पड़ा।

- **1.35 लाख रोजगार, 85 हजार कुशल इंजीनियर बनेंगे**

आईटी मंत्री ने कहा कि योजना के तहत 35 लाख प्रत्यक्ष और एक लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। कुलमिलाकर पांच साल में 1.35 लाख को रोजगार मिलेगा। दुनियाभर में काम कर रहे कुल इंजीनियरों में से 20 फीसदी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पीएलआई योजना के तहत चिप्स टू स्टार्टअप को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 85 हजार कुशल इंजीनियरों को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उत्पादन और विपणन से जुड़े लाखों अन्य रोजगार भी पैदा होंगे। चिप डिजाइनर तैयार करने के लिए डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना भी बनाई है, जिसमें खर्च का 50 फीसदी सरकार वहन करेगी। इतना ही नहीं इस डिजाइन को अन्य कंपनियों के साथ साझा करने पर इससे होने वाली बिक्री पर भी अगले पांच साल 6-4 फीसदी तक नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा।